इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 225

30 नवम्बर, 2015 को उत्तर के लिए

इस्पात का मूल्य

225. श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोहे की छड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात की कीमतों में गिरावट के क्या कारण हैं और देश में इसकी कीमतों में गिरावट के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायर राड की दरों का ब्यौर निम्नवत है:

(आंकड़े रु. प्रति टन)

माह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अप्रैल	50230	46500	48353	38260
मई	50640	46500	48208	39999
जून	49630	46250	48353	35741
जुलाई	49580	46250	48932	32993
अगस्त	49880	46000	43600	32304
सितंबर	49220	46710	43202	32517
अक्तूबर	48870	46600	42904	31139
नवंबर	48510	46760	39757	
दिसंबर	48660	47210	38251	
जनवरी	47360	47470	39527	
फरवरी	46960	47820	39248	
मार्च	46450	47520	39133	
मुम्बई की खुदरा कीमत पर आधारित कीमतें				*स्रोत: जेपीसी*

ख)	इस्पात मंत्रालय ने अपने दिनांक 12 मार्च, 2012, के आदेश के जरिए इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2012 अधिसूचित किया है जिसके माध्यम से ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू विनिर्माताओं को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट इस्पात एवं इस्पात उत्पादों जो या तो मानकों के अनुरूप नहीं हैं या जिन पर मानक चिह्न (बीआईएस या आईएसआई चिह्न) छपा नहीं है, के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण अथवा वितरण को प्रतिबंधित किया गया है।

ग)	इस्पात की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं और ये बाजार में विशिष्ट मांग और आपूर्ति की परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। स्वतंत्र विदेशी व्यापार के साथ वैश्विक रूप से एकीकृत बाजार होने के नाते इस्पात की कीमतें मुख्य रूप से वैश्विक बाजार में प्रचलित प्रवृतियों द्वारा निर्धारित होती हैं। वैश्विक इस्पात बाजार की पहचान इस्पात उद्योग के साथ-साथ संबंधित कच्चे माल वाले उद्योगों में बहुत अधिक क्षमता के विद्यमान होने से होती है। इन सभी कारकों ने इस्पात की कीमतों पर दबाव डाला है और इसी के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में निरन्तर गिरावट हो रही है। इस्पात बाजार एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार का उसकी कीमतों पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि, सरकार अनुचित व्यापार और सस्ते आयात से उद्योग की सुरक्षा के लिए उपयुक्त राजकोषीय उपायों के जरिये दखल देती है।

***